

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 994  
जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।  
19 माघ, 1944 (शक)

### सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र

994. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर :

श्री राजीव प्रताप रुडी :

श्री अरुण साव :

श्री दिलीप शइकीया :

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

श्री देवजी पटेल :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की योजना देश में टियर 2 और टियर 3 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की है और यदि हां, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर पूर्व राज्यों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार के पास बंगलौर, हैदराबाद, पुणे, मुम्बई आदि जैसे भारत के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
- (घ) यदि हां, तो बिहार के सारण जिले सहित इन केंद्रों में नियोजित लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जिला-वार संख्या का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार सहित इन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों में कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष कुल कितना प्रेषण किया जाता है ?

उत्तर

### इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): भारत सरकार, रोजगार के अवसर सृजित करने और यह सुनिश्चित करने कि प्रत्येक युवा भारतीय किसी भी स्थान से माननीय प्रधान मंत्री और सरकार के एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था दृष्टि में भागीदार बन सकता है देशभर में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने पर केन्द्रित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी,

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई), छोटे शहरों सहित पूरे देश में सरकारी पहलों का प्रसार करने में सहायक है। अब तक, देश भर में 63 एसटीपीआई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 6 एसटीपीआई केंद्र महाराष्ट्र में, 1 छत्तीसगढ़ में, 1 बिहार में, 11 पूर्वोत्तर राज्यों में और 2 राजस्थान में हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश भर में 22 नए एसटीपीआई केंद्रों को भी मंजूरी दी है। मौजूदा और स्वीकृत एसटीपीआई केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध-I और II** में दी गई है।

(ख): ये एसटीपीआई केंद्र प्लग-एन-प्ले सुविधा, केंद्रीकृत कंप्यूटिंग और हाई-स्पीड डेटा संचार सहित अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना, अक्टूबर, 2012 में इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और प्रसुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित की गई है। यह योजना अक्टूबर, 2017 से आवेदन प्राप्त करने के लिए बंद कर दी गई थी। इस योजना के तहत, देशभर के 15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) को मंजूरी दी गई थी। इन ईएमसी का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

देश में मजबूत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आगे की आवश्यकता के आधार पर, एमईआईटीवाई ने मार्च, 2023 तक आवेदन की प्राप्ति के साथ 1 अप्रैल, 2020 को संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना शुरू की है। ईएमसी 2.0 योजना के तहत, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य में ईएमसी परियोजना की स्थापना के लिए 3 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। इन ईएमसी का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस) भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बीपीओ/आईटीईएस संचालन की स्थापना के लिए प्रोत्साहन राशि देकर रोजगार के अवसर पैदा करना और छोटे शहरों/कस्बों में आईटी/आईटीईएस उद्योग का प्रसार करना था। नई बोलियों को आमंत्रित करने के लिए आईबीपीएस और एनईबीपीएस की अवधि क्रमशः 31.03.2019 और 31.03.2020 तक थी, हालांकि इस अवधि के बाद संवितरण जारी रह सकता है। इन योजनाओं के तहत देश के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 246 इकाइयों ने बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित किए हैं, जो 52065 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं।

देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति

(एनपीएसपी ) - 2019 को अधिसूचित किया गया है। एनपीएसपी के अनुसार , सरकार ने अगरतला, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, गुवहाटी, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मोहाली, पटना और विजयवाड़ा में स्थित 12 टियर II/III एसटीपीआई केंद्रों में सॉफ्टवेयर उत्पाद इन्क्यूबेशन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 95.03 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (एनजीआईएस ) को मंजूरी दी है। ।

**(ग) और (घ):** नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम ) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग ने वित्त वर्ष 2022 तक 5.1 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को रोजगार दिया था। हालांकि , आईटी उद्योग के कर्मचारी हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं जिसमें उनके पास कंपनी परिसर के बाहर किसी जगह से काम करने की छूट है और वे घर से काम करने का विकल्प भी चुन सकते हैं जो अलग राज्य में भी स्थित हो सकता है। इसलिए , आईटी कर्मचारियों को राज्य /संघ राज्य क्षेत्र - वार अलग करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

**(ड):** आईटी हब में कर्मचारियों द्वारा सालाना वापस भेजे गए कुल विप्रेषण संबंधी आंकड़े भारत सरकार द्वारा दर्ज नहीं किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

## मौजूदा एसटीपीआई केंद्रों की राज्यवार सूची

क्र.सं	राज्य	केंद्र का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा
2.		तिरुपति
3.		विजयवाड़ा
4.		विज़ाग
5.	असम	गुवहाटी
6.	बिहार	पटना
7.	छत्तीसगढ़	भिलाई
8.	गुजरात	गांधीनगर
9.		सूरत
10.	हरियाणा	गुडगाँव
11.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
13.		श्रीनगर
14.	झारखंड	रांची
15.		देवघर
16.	कर्नाटक	बेंगलुरु
17.		हुबली
18.		मंगलौर
19.		मणिपाल
20.		मैसूर
21.		दावणगेरे
22.	केरल	तिरुवनंतपुरम
23.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
24.		भोपाल
25.		इंदौर
26.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
27.		कोल्हापुर
28.		नागपुर
29.		नासिक

क्र.सं	राज्य	केंद्र का नाम
30.		मुंबई
31.		पुणे
32.	मणिपुर	इंफाल
33.	मेघालय	शिलांग
34.	मिजोरम	आइजोल
35.	ओडिशा	बेरहामपुर
36.		भुवनेश्वर
37.		राउरकेला
38.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
39.	पंजाब	मोहाली
40.	राजस्थान	जयपुर
41.		जोधपुर
42.	सिक्किम	गंगटोक
43.	तमिलनाडु	चेन्नई
44.		कोयंबटूर
45.		मदुरै
46.		तिरुनेलवेली
47.		त्रिची
48.	तेलंगाना	हैदराबाद
49.		वारंगल
50.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
51.		कानपुर
52.		लखनऊ
53.		नोएडा
54.		मेरठ
55.	उत्तराखंड	देहरादून
56.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
57.		हल्दिया
58.		खड़गपुर
59.		कोलकाता
60.		सिलीगुड़ी

क्र.सं	राज्य	केंद्र का नाम
61.	त्रिपुरा	अगरतला
62.	गोवा	गोवा
63.	नगालैंड	कोहिमा

स्वीकृत नए एसटीपीआई केंद्रों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	जगह
1.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
2.		जबलपुर
3.	पंजाब	अमृतसर
4.	झारखंड	धनबाद
5.		जमशेदपुर
6.		बोकारो
7.	उत्तर प्रदेश	औरंगाबाद
8.		वाराणसी
9.		गोरखपुर
10.		बरेली
11.	केरल	कोच्चि
12.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
13.	ओडिशा	बालासोर
14.		संबलपुर
15.		जाजपुर
16.		अंगुल
17.		कोरापुट (जयपोर)
18.	बिहार	दरभंगा
19.		भागलपुर
20.	हरियाणा	पंचकुला
21.	गुजरात	भावनगर
22.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा



अनुबंध- III

क्र. सं	राज्य	स्थान	क्षेत्र (एकड़)	अनुमोदन की तिथि	कार्यान्वयन एजेंसी	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	
						परियोजना की लागत	सहायता अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	श्री सिटी, सत्यवेदु मंडल, चित्तौड़ जिला	94	20.07.2016	श्री सिटी ईएमसी प्रा. लिमिटेड	56.75	27.34
2		ईएमसी -1 @ तिरुपति, रेणिंगुटा और येरपडु मंडल, चित्तौड़ जिला	113.27	07.12.2017	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	74.27	37.13
3		ईएमसी -II @ तिरुपति, विक्रुतमाला गांव, येरपडुमंडल, चित्तौड़ जिला	501.40	02.08.2017	(एपीआईआईसी )	248.89	98.46
4	असम	बोंगोरा, कामरूप जिला, असम	100	01.02.2018	असम इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड (एमट्रॉन)	119.85	50
5	छत्तीसगढ़	सेक्टर-22, नया रायपुर	116.48	07.01.2016	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	103.88	43.08
6	गोवा	तुएम, उत्तरी गोवा जिला	147.55	03.03.2017	आईटी विभाग, गोवा सरकार	161.32	73.77
7	गुजरात	मुंद्रा, कच्छ जिला	631.38	04.07.2016	मुंद्रा सोलर टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड (एमएसटीपीएल )	745.14	315.69
8	झारखंड	आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां जिला	82.49	22.09.2015	झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जेआईएडीए)	97.88	41.48
9	केरल	कक्कनाड, एर्नाकुलम जिला	66.87	24.08.2016	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा)	35.06	15.89
10	मध्य प्रदेश	बड़वई-भोपाल	50	25.08.2014	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड	47.19	20.86
11	मध्य प्रदेश	पुरवा-जबलपुर	40	25.08.2014	निगम लिमिटेड	38.57	17.76

	प्रदेश				(एमपीएसईडीसी)		
12	ओडिशा	एन्फोवैली, भुवनेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, खुर्दा जिला	203.37	05.09.2016	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	200.76	93.09
13	राजस्थान	सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, खुशकेरा, भिवाड़ी	50.3	15.09.2015	एलिसना इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर प्रा. लिमिटेड (ईईएमसीपीएल)	46.09	20.24
14		करोली औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला-अलवर	121.51	15.12.2017	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	29.13	11.49
15	तेलंगाना	ई-सिटी, हैदराबाद	603.52	02.08.2017	तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (टीएसआईआईसी)	667.6	252.42
16		महेश्वरम, रंगा रेड्डी	310.70	08.08.2017	इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (टीएसआईआईसी)	436.97	138.6
17	उत्तर प्रदेश	इकोटेक-VI औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा	99.41	21.02.2018	टेगना इलेक्ट्रॉनिकी प्रा. लिमिटेड (टीईपीएल)	115.32	50
18	पश्चिम बंगाल	फाल्टा, दक्षिण 24 परगना जिला	58.04	04.02.2016	पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास निगम लिमिटेड (वेबईएल)	58.86	25.64
19	पश्चिम बंगाल	नैहाटी, उत्तर 24 परगना जिला	70	31.08.2016	लिमिटेड (वेबईएल)	58.31	25.7
20	कर्नाटक (सीएफसी)	हेब्लल औद्योगिक क्षेत्र, मैसूर	1.50	15.09.2015	मैसूर ईएसडीएम क्लस्टर	48.53	32.31
21	महाराष्ट्र	शेंद्र औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद जिला	1.98	03.03.2017	देवगिरी इलेक्ट्रॉनिकी क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड (डीईसीपीएल)	41.09	29.29
22		पिंपरी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे	0.61	13.12.2017	एमसीसीआईए इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर फाउंडेशन (एमईसीएफ)	67	50

अनुबंध- IV

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षेत्र (एकड़)	अनुमोदन की तिथि	कार्यान्वयन एजेंसी	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	
						परियोजना की लागत	सहायता अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	कोप्पार्थी गांव, कडप्पा वाईएसआर जिला	540	18.02.2021	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी)	748.76	350
2	हरियाणा	औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) सोहना, नूंह जिला	500	30.09.2021	हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी)	662.08	331.04
3	महाराष्ट्र	रंजनगांव चरण - III, पुणे जिला	297.11	31.10.2022	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी)	492.85	207.98

\*\*\*\*\*